अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के लिए मकान बनाने पर खर्च किया जाएगा। इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत जिला-वार बनाए गए मकानों की निगरानी केन्द्रीय स्तर पर नहीं की जाती है। तथापि, 1991–92 से 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकानों की संख्या निम्नलिखित है :–

वर्ष	इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकानो की संख्या
1991–92	40644
1992–93	47156
1993–94	48108

(ख) जी, हां।

मध्य प्रदेश के लिए ग्रामीण विकास योजनायें/परियोजनायें

5996. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कितनी ग्रामीण विकास योजनायें और परियोजनायें केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं और उन का जिलेवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन योजनाओं/परियोजनाओं पर जिलेवार कब तक मंजूरी दे दी जायेगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के **(ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एम० पटेल)** : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और भूमि सुधार के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के लिये स्वीकृति हेतु लंबित ग्रामीण विकास परियोजनाओं/योजनाओं की संख्या निम्नानुसार है :–

1. **जवाहर रोजगार योजना**

विशेष और अभिनव परियोजनाओं से संबंधित जवाहर रोजगार योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत मध्य प्रदेश के खारगांव जिले के बरवानी खण्ड में बापनगजा पहाड़ियों के पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने नामक एक परियोजना स्वीकृति हेतु लंबित है। जांच समिति की जब कभी चालू वर्ष के दौरान बैठक होगी तब इस परियोजना पर विचार किया जाएगा।

2. **त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम :**

मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त निम्नलिखित चार योजनायें विचाराधीन हैं :–

(1) मोरेरा जिले में करहाल खण्ड के लिये जल संरक्षण एवं संपूर्ति परियोजना।

(2) राजगढ़ जिले में समेकित जल संपूर्ति जल संरक्षण परियोजना।

(3) धार जिले के लिये जल संरक्षण एवं संपूर्ति परियोजना।

(4) शाजापुर जिले के लिये जल संरक्षण परियोजना।

उपरोक्त परियोजनाओं की स्वीकृत करने हेतु शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की संभावना है।

3. **भूमि सुधार :**

मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त निम्नलिखित दो परियोजनायें विचाराधीन हैं :–

(1) राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत तकनीकी स्वीकृति और निधियों को रिलीज हेतु 541.46 लाख रुपये की लागत वाला एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(2) चार जिलों अर्थात सीधी, विदिशा होशंगाबाद और बिलासपुर के लिये 114.50 लाख रुपये की लागत वाला भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु एक प्रस्ताव भूमि

अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की केन्द्रीय सेक्टर की योजना के अंतर्गत अनुमोदन और निधियों की रिलीज के लिये प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त दोनों प्रस्तावों की जांच की जानी है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित निधियों के रिलीज कर दिये जाने की संभावना है।

Wasteland in Gujarat

5997. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the total area of Wasteland in Gujarat as on date, district-wise;

(b) whether there is any proposal to reclaim the wasteland in phases and bring the land under tree plantation during 1993-94 and 1994-95; and

(c) if so, the district-wise details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WASTELANDS DEVELOPMENT) (COL. RAM SINGH): (a) No detailed district-wise survey has yet been conducted for identification of wastelands in Gujarat State but according to one estimate the total extent of wastelands in Gujarat is 78.36 lakh hectares. However, the Department of Wastelands Development has commissioned National Wastelands Identification Project with the collaboration of the National Remote Sensing Agency. Under this programme 147 districts with more than 15 per cent of wastelands and 82 districts with more than 5 per cent of wastelands but less than 15 percent were mapped in different phases. In Gujarat the districts of Rajkot, Kheda, Surendranagar, Bhavnagar, Ahmedabad, Mahesana, Panch Mahals, Junagadh, Jamnagar and Gandhinagar have more than 15 per cent of wastelands. The districts having more than 5 percent of wastelands and less than 15 per cent are Amreli, Banaskantha and Sabarkantha.

(b) and (c) Afforestation/Tree planting activities on lands including State of Gujarat under the point no, wastelands are being carried out in the 16 of the 20 Point Programme through the various Central and State Government Schemes. The target under this programme are fixed, State-wise on year to year basis depending upon the availability of funds. The following progress on afforestation/tree planting under point no. 16 of the 20 Point Programme for the year 1993-94 in the State of Gujarat has been achieved.

(Seedlings in Lakhs
Area in Hectares)

Target		Achievement	
Seedlings Distribution (for planting on private lands)	Area Coverage (Public lands including forest lands)	Seedlings Distribution (for planting on Private lands)	Area Coverage (public lands including forest lands)
1500.00	68,000.00	1631.76	35277.00

The targets for the year 1994-95 are yet to be finalised.